भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4487

उत्तर देने की तारीख- 27/03/2025

दादरा और नगर हवेली में ईएमआरएस की स्थापना

4487. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली में जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान दादरा और नगर हवेली के जिलों में ईएमआरएस की स्थापना के लिए स्वीकृत कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा जनजातीय छात्रों को खेलों में बढ़ावा देने तथा उनकी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बेहतर मंच प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 तक देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ग): 2018-19 के केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में एक ईएमआरएस को अनुमोदन दिया है। उक्त ईएमआरएस 2020-21 से कार्यात्मक है। इसलिए चालू वर्ष के दौरान ईएमआरएस की स्थापना के लिए कोई निधियां स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(घ): ईएमआरएस में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। प्रतिभागियों का चयन उन राज्यों में आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से किया जाता है जहाँ ईएमआरएस क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी धनुर्विद्या परियोजना के भाग के रूप में, प्रतिभाशाली तीरंदाजों को विकसित (तैयार) करने और उन्हें अगले ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करने पर जोर देने के साथ विशेष अनुदेश प्रदान करने हेतु भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के साथ साझेदारी में तीरंदाजी केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, ईएमआरएस में खेल सुविधाएँ (इनडोर और आउटडोर) प्रदान की जाती हैं और नई योजना के तहत बनाए जा रहे सभी ईएमआरएस में तीरंदाजी रेंज का प्रावधान भी किया गया है।

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2025-26 तक देश भर में 728 ईएमआरएस स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाकर कई प्रमुख उपाय किए हैं:

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ईएमआरएस के प्रबंधन के लिए, एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (एनईएसटीएस) द्वारा निम्नलिखित उपायों को अपनाकर प्रक्रिया का सरलीकरण:

(i) ईएमआरएस कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को शामिल करने वाली विस्तृत संरचना (ढांचा) तैयार की गई है।

(ii) ईएमआरएस के निर्माण के लिए 15.00 एकड़ भूमि क्षेत्र के प्रावधान में शिथिलता (ढील)

(iii) प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय मंजूरी और डीपीआर के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधियों का विपथन न हो तथा वह केवल निर्दिष्ट परियोजना के लिए ही उपलब्ध हो, परियोजना वार एस्क्रो खाते खोले गए हैं।

(2) केंद्रीय स्तर पर प्रगति की नियमित निगरानी एनईईटीएस के माध्यम से की जाती है और राज्य स्तर पर निगरानी राज्य जनजातीय विभागों की राज्य समितियों द्वारा की जाती है। इसके अलावा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति जिला स्तर पर ईएमआरएस की प्रगति की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, ईएमआरएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भुमि की पहचान और आवंटन तथा प्रगति में तेजी लाने के लिए एनईएसटीएस और मंत्रालय निर्माण एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करते हैं तथा राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हैं।

(3) गुणवत्ता निगरानी:

(i) ईएमआरएस के निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

(ii) ईएमआरएस के निर्माण के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों जैसे सीबीआरआई रुड़की, आईआईटी रुड़की का नियोजन।

*****